

## संशोधित अनुमान 2013-2014

वर्ष 2013-14 का संशोधित अनुमान बजट अनुमानों में ₹ 74,863 करोड़ की निवल गिरावट को दर्शाता है। आयोजना-भिन्न व्यय में ₹ 4,927 करोड़ की वृद्धि देखी गई है और आयोजना व्यय में ₹ 79,790 करोड़ की गिरावट हुई है। अन्तर की विविध प्रमुख मदों को नीचे दर्शाया जा रहा है:-

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2013-14	संशोधित 2013-14	घट-बढ़ बचत(-)/ आधिक्य(+)
<b>आयोजना-भिन्न</b>			
1. पेट्रोलियम सब्सिडी	65000	85480	(+)20480
2. ब्याज भुगतान तथा ऋण चुकाना	370684	380066	(+) 9382
3. पेंशन	70726	74076	(+) 3350
4. पुलिस	40895	43148	(+) 2253
5. खाद्य सब्सिडी	90000	92000	(+) 2000
6. उर्वरक सब्सिडी	65971	67971	(+) 2000
7. लाभांश राहत के लिए रेलवे को सब्सिडी	2746	3530	(+) 784
8. पूंजी परिव्यय (रक्षा को छोड़कर)	30131	7804	(-)22327
9. राज्य सरकारों को अनुदान	76105	60762	(-)15343
10. डाक घाटा	6717	5880	(-) 837
11. अन्य आयोजना भिन्न व्यय	291000	294185	(+) 3185
<b>जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय</b>	<b>1109975</b>	<b>1114902</b>	<b>(+) 4927</b>
<b>आयोजना</b>			
1. केन्द्रीय आयोजना	419068	356493	(-)62575
2. राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	136254	119039	(-)17215
<b>जोड़ आयोजना व्यय</b>	<b>555322</b>	<b>475532</b>	<b>(-)79790</b>
<b>कुल व्यय</b>			
<b>(आयोजना + आयोजना-भिन्न)</b>	<b>1665297</b>	<b>1590434</b>	<b>(-)74863</b>

## आयोजना-भिन्न

- यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर कम वसूली और एलपीजी स्कीम के प्रत्यक्ष अंतरण को क्रियान्वित करने हेतु तेल विपणन कंपनियों को अधिक मुआवजा देने के कारण है।

- बाजार ऋण, नकदी प्रबंधन विधेयक, राजकोषीय हुण्डी लघु बचत संग्रहणों के विरुद्ध जारी प्रतिभूतियों, भविष्य निधियों और गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमा राशियों पर ब्याज भुगतान के कारण अधिक आवश्यकता हुई।
- सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिक, सिविल पेंशनभोगियों और बीएसएनएल में समाहित कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ हेतु पेंशन भुगतान के लिए अधिक आवश्यकता के कारण इसमें बढ़ोतरी हुई।
- आंतरिक सुरक्षा संबंधी अधिक आवश्यकताओं के कारण इसमें वृद्धि हुई।
- यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त प्रावधान करने के कारण हुई।
- देसी (यूरिया) उर्वरकों के अंतर्गत अधिक आवश्यकता के कारण।
- यह वृद्धि सामान्य राजस्व को रेलवे द्वारा देय लाभांश की दर में संशोधन तथा रेलवे को देय सब्सिडी में तदनु रूप वृद्धि होने के कारण हुई।
- यह कमी मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में कम निवेश के कारण आई।
- यह कमी राज्य सरकारों को अनुदान जारी करने की कम आवश्यकता के कारण आयी।
- डाक घाटा में कमी राष्ट्रीय बचत का कार्य करने हेतु एजेंसी प्रभागों के भुगतान में वृद्धि के कारण आयी।

## आयोजना

- समग्र कमी, कृषि, परमाणु ऊर्जा, औद्योगिक नीति और संवर्धन, डाक और दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण और वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, उच्चतर शिक्षा, श्रम और रोजगार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, अल्पसंख्यक मामले, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, योजना, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, भू-संसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सीएसआईआर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, कपड़ा, शहरी विकास, जल संसाधन तथा महिला और बाल विकास में आयोजना आवंटन में कमी के कारण हुई।
- समग्र कमी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि तथा संघ राज्य राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के कारण हुई।